compared to the target to be achieved by 1990, are as follows:—

Category of Centre	Coverage Criteria	Percentage coverage as per targets fixed for 1990
Sub-Centres	1 for every 3000—5000 population	86
Primary Health Centre . . .	1 for every 20000—30000 population	78
Community Health Centres . .	1 for every 1 lakh to 1.2 lakh population.	54

By 1990, 100% coverage of sub-centres and Primary Health Centre is likely to be achieved.

Purchase of MK-428 Anti-submarine Warfare Helicopters

3222. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :
SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH :
SHRI BHAGATRAM MANHAR :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has given their acceptance for the purchase of MK-42B Anti-submarine Warfare (ASW) helicopters for Naval carrier "Viraat" ;

(b) if so, what are the details in this regard ;

(c) what is the total cost of MK-42B's being purchased by the Indian Government and to what extent it will be better than sea king helicopters:

(d) whether it is also a fact that its performance is not upto the standard ; and

(e) if so, what action Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI) : (a) to (e) Mark 42B helicopters, being acquired for the Indian Navy, are modern anti-submarine helicopters which can also be armed with anti-ship missiles. The helicopters are being accepted after trials and it is ensured that they conform to the specified standards. Further details cannot be divulged for reasons of national security.

Warning against use of Drugs containing AIDS Virus

@ 3222-A. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Drug Controller of India has recently cautioned hospitals and doctors against the use of two drugs manufactured by a Bombay firm as there were indications that they contained the AIDS virus as reported in the Indian Express of 11th February, 1989 ;

(b) if so, whether any action has been taken by Government against the manufacturers of these drugs ; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

@Previously Unstarred Question No. 2953 transferred from the 27th March, 1989.

THE MINISTER OF TEXTILES AND THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Yes.

(b) and (c) The Commissioner, Food and Drugs Administration, Maharashtra took steps to stop further production and distribution of all blood products by the firm and to recall from the market all the stocks of anti-D immunoglobulin injections.

The Drug Controller of Delhi took action to freeze stocks of batch No. 6/88 of anti-D immunglobulin injections.

Particulars of the distribution of batch no. 6/88 were given to the State Drug Controllers and they were requested to steps to freeze the stocks and also to ensure withdrawal of stocks from Government Hospitals and nursing homes.

औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास व्यय

@3222-डॉ. श्री राम सरेश यादव :
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 दिसम्बर, 1988 के टाइम्स आफ इंडिया में "आर एन डी एक्सपेंडिचर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर नाट एनकरेजिंग फिक्की" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर जो धनराशि खर्च की जा रही है उसका अधिक भाग सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश के सरकारी उद्योगों का हिस्सा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में अधिक है ; और

(घ) क्या उक्त समाचार में कोई सुझाव भी दिए गए हैं, यदि हां, तो क्या सरकार दिए गए सुझावों के अनुरूप एक योजना तैयार करने की विचार रखती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में अनुसंधान व विकास व्यय का पर्याप्त भाग (लगभग 80%) सरकार द्वारा अपने प्रमुख अनुसंधान अभिकरणों के अंतर्गत प्रयोगशालाओं की श्रंखलाओं के माध्यम से व्यय किया जाता है। स्वयं उद्योग (इण्डस्ट्री) द्वारा उद्योग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर उद्योगों में अनुसंधान व विकास इकाइयों की स्वीकृति के लिए योजना है। वर्ष 1987–88 में अपने यहां (इन हाउस) 1000 अनुसंधान व विकास इकाइयों में 600 करोड़ रुपए का अनुमानित किया व्यय जो राष्ट्रीय अनुसंधान व विकास व्यय का लगभग 20% था। सरकारी संयुक्त क्षेत्रों की लगभग 100 स्वीकृत घरेलू (इन हाउस) अनुसंधान व विकास इकाइयों ने 240 करोड़ रुपए व्यय किए, 900 गैर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया गया व्यय 360 करोड़ रुपए था। वर्ष 1984–85 में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का हिस्सा 61% था तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का हिस्सा लगभग 30% था।

(घ) फिक्की रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए थे जिनमें अनुसंधान संस्थानों

@ तारांकित प्रश्न संख्या 2991 27 मार्च, 1989 को से स्थानान्तरित